

भाग चार : खण्ड 3

1. अनुसूचित जनजाति तथा वन में परम्परा से रहने वाले वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006

(ब. 2 वर्ष 2007)

वन में रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा वन में परम्परा से रहने वाले अन्य व्यक्ति को, जो वन में पीढ़ियों से रह रहे हैं तथा वन भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, परन्तु उनके अधिकार कभी भी अभिलिखित नहीं किये गये। उनके वन भूमि के अधिकारों को अभिलिखित करने, और उनको रूपाय करने हेतु, किस साधन की आवश्यकता होगी और ये अधिकार किस प्रकार मान्य तथा रूपाय किये जावेंगे, यह निर्धारण करने तथा उनके अधिकारों को मान्यता देने व अधिकार देने हेतु अधिनियम।

जबकि वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा वन में परम्परा से रहने वाले अन्य व्यक्ति को वन में रहने का अधिकार रूपाय करने से उनकी वन भूमि को लगातार उपयोग करने का दायित्व तथा अधिकार प्राप्त होता है उसके साथ उनकी वन जैविक विभिन्नता वाले पशु तथा पौधे तथा पर्यावरण संतुलन का संरक्षण तथा सुरक्षा का दायित्व भी आवेगा, जो वन के संरक्षण क्षेत्र की वृद्धि करेगी तथा वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा वन में परम्परागत रहने वाले अन्य व्यक्ति की रहने की तथा भोजन की सुरक्षा करेगा।

और जबकि राजाओं के राज्यकाल में तथा बाद में : वतन्ता के पंचात् भी राज्य के वनों के पुनर्गठन के समय, वन में पीढ़ियों से रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा अन्य व्यक्ति के उनकी पीढ़ियों से कब्जे की वन भूमि के अधिकारों को समुचित मान्यता नहीं दी गई जिससे वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ जबकि वे वन की इकोसिस्टम को बचाने तथा लगातार बने रहने के एक अंग हैं। और अब वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्ति को तथा उनको, जिन्हें राज्या के विकास कार्यों हेतु अपने रहने के : थान को जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, उनको उस भूमि की धृति तथा पहुँच के प्रति लम्बे समय से चली आ रही असुरक्षा को समाप्त करने का समय आ गया है अतः

भारत के गणराज्य के 57 वे वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो -

अध्याय 1

प्रारम्भिक

(1) संक्षिप्त नाम तथा लागू होना - (1) यह अधिनियम "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" कहलावेगा।

(2) यह अधिनियम पूरे भारत में, जम्मु कश्मीर राज्य छोड़कर, लागू होगा।

(3) यह अधिनियम उस दिनांक से, जो केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, लागू होगा।

नोट - यह नियम 31.12.77 से लागू हुआ है।

(2) परिभाषाएँ - जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो -

(a) समुदाय के वन स्रोत (Community Forest Resource) से तात्पर्य है किसी गांव की सावर्जनिक वन भूमि जो परम्परागत या रीतिरिवाज के अनुसार गांव की सीमा के अन्दर स्थित है या चरवाहे जाति के मामले में वह वन वनभूमि जिसका उपयोग ऋतु अनुसार होता हो, जिसमें आरक्षित वन संरक्षित वन या सुरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य, या रां शीय उद्यान भी सम्मिलित हैं, जिस पर उनकी परम्परागत पहुँच हो।

1. इस अधिनियम को रां शपित की : वीकृति 29.12.06 को प्राप्त हुई। अधिनियम भारत शासन के राजपत्र (असाधारण) भाग-II-सेक्शन-1 दि. 2.1.07 पृष्ठ 1-9 पर प्रकाशित।

(b) वन प्राणी खतरे वाली आवासीय भूमि (Critical wild life habitat) से तात्पर्य रां शीय उद्यान या अभयारण्य के वे क्षेत्र, जिन्हें वैज्ञानिक तथा विविध उद्देश्यीय मापदण्ड से, विशिष्ट रूप से, : पटतया निश्चित हो गया है कि ऐसे क्षेत्रों को वनप्राणी के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जावे।

जिनके सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की राय ली जावेगी, और जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मिलित रहेंगे जिन्हें राज्य शासन नियुक्त करे, तथा एक सदः य अनुसूचित जनजाति कार्य मन्त्रालय का प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जावेगा और धारा 4 के उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार निश्चित किया जावेगा कि कया भूमि को वन प्राणी संरक्षण हेतु सुरक्षित किया जावे। पंचात् केन्द्र शासन, के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित किया जावेगा।

(c) 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति' से तात्पर्य अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदः यों से हैं जो मुख्य रूप से वन में रहते हैं और वे उनके जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर रहते हैं और जिनमें चरवाहे जाति के सदः य भी सम्मिलित हैं।

(d) वन भूमि (Forest land) में वह वन भूमि जो किसी भी परिभाषा से जानी जाती हो और वन में : स्थित हो जिसमें अवगीकृत वन, (unclassified forest), जिसकी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ हो ऐसे वन

(undermarked forests) या िजनको वन माना गया हो, या संरक्षित वन आरक्षित वन, अभ्यारण्य और रां शीय उद्यान सिमिलत है।

- (e) वन अधिकार (Forest right) से तात्पर्य उन वन अधिकारों से है जो खण्ड 3 में दिये हैं।
- (f) 'वनमाम' वह व्यवस्थापन जो वन के अन्दर किसी राज्य के वन विभाग द्वारा वन कार्योर् के सम्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो, या िजन् हें वन के आरक्षण की रूबिया में वनमाम बनाया गया हो और िजन्में सिमिलत है वन बन् दोब: त माम, िनिश्चित मांग के कब्जे (fixed demand holding) वाली भूमि सभी प्रकार के टाग या व्यवस्थापन, चाहे िजस नाम से जाने जाते हो तथा िजसमें वह वन भूमि सिमिलत है िजस पर राज्य शासन के खेती करने की अनुमित ही है।
- (g) माम सभा- से तात्पर्य गांव की वह सभा िजसमें गांव के सम: त रूढ सिमिलत हो और उन राज्यो के सम्बन्ध में जहाँ पंचायत, पड़ाव, टोला और अन्य पारम्परिक माम सं: था न हो वहाँ मामवासियों द्वारा चयनित सभा िजसमें मिहला का भाग लेना रूढिबिन्धत न हो।
- (h) रूढाकृतिक वास (Habitat) में वह क्षेत्र सिमिलत है जो आरक्षित या संरक्षित वन में अविकसित जनजाति के सद: यों का और जो कृषि कार्य के रूढारम्भ के पूर्व की जातियों की अनुसूचित जनजातियों का वास: थान है।
- (i) लघु वन उपज (Minor Forest Produce) में सिमिलत है वृक्षों के इमारती भाग को छोड़ सम: त भाग और िजसमें बांस, झाड़ी, टूढ़, बेत, टसर, ककून, शहद, मोम, लाख, तेन्दु या केन्दुपत्ता, औषधीय पौधे, छोटे पौधे (Herb) जड़ें, गाँठ (tumer) और उस प्रकार की व: तुए सिमिलत हैं।
- (j) नोडल एजेन्सी से तात्पर्य वह एजेन्सी है जो सेक्शन 11 में दी गई है।
- (k) अधिसूचना (Notification) से तात्पर्य वह अधिसूचना है जो शासकीय राजपट में रूकाशित हो।
- (l) 'निधारित' से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों में रूावधानित है।
- (m) "अनुसूचित क्षेत्र" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 244(1) में दिया गया क्षेत्र है।
- (n) लगातार उपयोग (Sustainable use) वह वही अर्थ होगा जो बायोलोजिकल डायवर्सिटी अधिनियम 2002 की धारा 2 के क्लोज (o) में दिया है।
- (o) "अन्य परम्परागत वनवासी" से तात्पर्य कोई व्यक्ति या समाज से है, जो 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व तीन पीढ़ियों से वन में रह रहा है, तथा जो वन या वन भूमि पर अपनी मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं के लिए िनभर है।
ः पंटीकरण - इस खण्ड में 'पीढ़ी' से तात्पर्य है 25 वर्ष का समय
- (p) गाँव से तात्पर्य है -
(i) Provision of Panchayat (extension to scheduled areas) Act 1946 की धारा 4 क्लोज (b) में दिया गया गाँव
(ii) किसी भी राज्य के पंचायत से सम्बन्धित कानून (अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर) में दिया गाँव
(iii) वन माम, पुरानी बसाहट, या बन् दोब: त, या िबना सवेर किया गाँव, चाहे गाँव के रूप में अधिसूचित हुआ हो या न हुआ हो।
(iv) उन राज्यो में जहाँ पंचायत न हो परम्परागत गाँव, चाहे िजस नाम से पुकारा जावे।
- (q) "वन्य पशु" से तात्पर्य वन रूाणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में दिये अनुसूचि I से IV में दी रूजाति और जो रूकृति में जंगल में िमलती हो।

अध्याय II

वन अधिकार (Forest Rights)

(3) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, और अन्य परम्परागत वनों में िनवास करने वालों के वन अधिकार -

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि पर रहने वाली अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय या दोनों को िनम्न वन अधिकार होंगे -

- (a) वन में रहने वाली अनु. जनजाति एवं परम्परागत वन में रहने वालों को वन की भूमि को धारण करने तथा उस पर एक व्यक्ति या समुदाय के रहने या जीवन यापन के लिए उस पर ः वयं या सद: यों द्वारा कृषि करने का अधिकार।
- (b) सामुदायिक अधिकार जैसे िन: तार या िजस किसी नाम से जाने जावे, या वे अधिकार जो वे पुराने राजाओं के, जमींदारी के या अन्य अन्तिम शासन के समय में रूापत कर रहे थे।
- (c) माम से या माम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम्परागत रूप संमिहत करते आ रहे हैं, संमहण करने या उस तक पहुँचने या उस पर मालिकाना अधिकार रखने उसको उपयोग में लाने का अधिकार।

- (d) जंगल के अन् दर पानी के अन् दर के पदाथर् जैसे मछली या अन् य पदाथर् पर अधिकार तथा वहां के
: थापित वासियों एवं पिरवहन करने वाले वन वासियों के और घुमक् कड़ और चरवाहा ूजाति के
वन में चराई अधिकार।
- (e) आदमकाल या कृषि काल के पूर्व के आदम जाति के समूहों का वन में रहने का अधिकार।
- (f) किसी राज्य की विवादमः त भूमि पर (जो राज्य में किसी नाम से जानी जाती हो) पर अधिकार।
- (g) किसी राज्य सरकार या अन् य : थानीय अधिकारी द्वारा ूदत् त वन भूमि के पट्टे या अनुदान के
द्वारा ूदत् त अधिकार को पिरवर्तन करने का अधिकार।
- (h) सभी वन मामों, पुराने वन के वास : थल, असीमा वाले गांव या वन में बसे किसी माम, चाहे
रिकाडर में हो या अधिसूचित हो या नहीं, का व्यवः थापन एवं उनको राजः व गांव में पिरवर्तन करने का
अधिकार।
- (i) किसी सामुदायिक वन की रक्षा करने, उसमें पुनरात् पदन करने, उसको सुरक्षित रखने या व्यवः
थापन करने का अधिकार।
- (j) वे अधिकार, जो किसी राज्य के या किसी : वायत् त क्षेत्रीय कौंसिल के कानून से या जिन्हें
जनजातियों के परम् परागत या रीतिरवाज के रूप में किसी जनजाति के लिए, किसी राज्य द्वारा
: वीकार किये गये हैं, का उपयोग करने हेतु।
- (k) किसी विंशं ट पौधे या पशु के सम् बन् ध में विशेष ज्ञान या परम् परागत ज्ञान या सांः कृतिक ज्ञान
हो उस पर पहुँच।
- (l) उपरोक् त (a) से (k) तक में दिये के अतिरक् त अन् य कोई परम् परागत या रीति रिरवाज अनुसार
अधिकार जो वन में वास कर रही आदम जनजाति या अन् य परम् परागत निवासियों द्वारा उपयोग
में लाया जा रहा हो, जिसमें वन में शिकार, वन्य पशु को पकड़ना, या किसी वन्य पशु का वन्य
पौधे का कोई अंग निकालना सम्मिलित नहीं है।
- (m) 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व विजन अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा अन् य वनवासियों को, विजनकी
वहां रहने की कानूनी पाऽता नहीं थी वन भूमि से हटाया गया, तथा भूमि का कब् जालिया, उपको पुनः
उसी : थान पर बसाने का अधिकार।
- (2) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (वर्ष 1980 का 69) में कोई बात होते हुए भी केन् ि शासन उस वन भूमि को,
जिसका ूबन् ध शासन कर रहा हो और जिस पर 75 वृक्ष ूति हेक् टयर से अधिक वृक्ष की कटाई न होना हो, को निम्न
न कार्यों के लिए, ूत् यावर्तन करने की अनुमित देगी -
- (a) पाठशाला
(b) अः पताल या िडः पेन् सरी
(c) आंगनवाड़ी
(d) उचित मूल्य की दुकान
(e) विद्युत एवं टेलीफोन लाइन
(f) तालाब या अन् य जल ूत
(g) पीने के पानी का ूदाय और पानी की पाइप लाइन डालना(h)
वषार् जल/जल संमहण के साधन
(i) लघु िसंचाई नहर
(j) अपरम् परागत उजार् का ूत
(k) उद्योग ूशिक्षण संः था
(l) सड़क
(m) सामुदायिक केन् ि
- परन् तु वन भूमि का ूत् यावर्तन में : वीकार किया जावेगा -
- (i) किसी भी कार् हेतु वन भूमि का क्षेत्र जो ूत् यावर्तन होना हो - एक हेक् टर से अधिक नहीं होगा।(ii)
किसी भी क्षेत्र की विकास हेतु, सफाई के पूर्व, उस गांव की गांव सभा द्वारा िसफारिश की गई हो।
- अध्याय III
वन अधिकारों को मान्यता देना, उनका पुनः : थापन, एवं अन् य सम् बिन्धित विषय
- (4) वन में रह रहे अनु. जनजाति के व्यक्ति एवं परम् परागत वन में निवास करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों
के मान्यता देना और उनको देना - तत् समय लागू किसी भी विधि में कोई भी ूावधान होते हुए भी और इस अधिनियम
के ूावधान अनुसार, केन् ि शासन निम्न अधिकारों को मान्यता देते हुए उनमें वेष्ठित करता है।

(a) राज् य के उन वन में रहने वाले अनु.जाति के सदः यों को, िजस ः थान के आदम जाति घोषित िकये गये हैं, धारा 3 में िदये समः त अधिकार।

(b) अन् य परम् परागत वन में िनवास करने वाले व् यक्तियों को धारा-3 में िदये समः त अधिकार।

(2) इस अधिनियम के अन् तर्गत यदि अधिकारों की मान् यता वन ूाणी के आवास ः थल, रां शीय उद्यान, या अभ् यारण् य के मध् य िःथत जनजाति के सदः यों को वेिष्ठत होते हैं तो उनको संशोिधत िकिया जावे या उनका पुनः ः थापन िकिया जावे। परन् तु वन ूाणी संरक्षित क्षेऽ को अन अतिबिभर्त क्षेऽ करने के िलए िकसी भी अधिकारी ूदत् त व् यक्त को पुनः ः थापित या अधिकारों में पिरवर्तर्न तब तक नहीं िकिया जावेगा, जब तक िक िनम् न शतेर् पूरी न कर ली जावे अथार्त-

(a) धारा 6 के अन् तर्गत अधिकारों की मान् यता देने और वेिष्ठत करने की ूबिया, िवचाराधीन ः थान के िलये पूरी न कर ली जावे।

(b) जब तक राज् य शासन के अधिकारी, वन ूाणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन् तर्गत ूदत् त शिक्त के आधार पर परीक्षण कर यह घोषित नहीं करते हैं िक अधिकार ूदत् त व् यक्तियों के वहाँ रहने का ूभाव उस ः थान में पाये जाने वाले वन् य पशु को अक्षित पूितर् योग् य हािनि पहुँचावेगा और उनका उस वास ः थान पर रहने का खतरा पैदा हो जावेगा।

(c) राज् य सरकार ने यह अन्तम िनणर्य ले िलया है िक वन् य ूाणी तथा अधिकार ूदत् त आदवासी का साथ रहने का कोई िवकल् प शेष नहीं है।

(d) पुनः ः थापना के ः थल को तैयार कर िदिया गया है और यह बता िदिया गया है िक वह ः थान पुनः ः थापित व् यक्तियों एवं समुदाय को सुरिक्षत जीवन यापन का साधन देगा और उनको सम् बिन्धत अधिनियम तथा केन् ि शासन की नीति अनुसार सुविधाये देने हेतु सक्षम है। (e) इस बसाहट और उसको िदये अधिकारों के िवषय में उस क्षेऽ की माम सभा को जानकारी देकर उनकी िलिखत सहमित ूाप् त कर ली गई है।

(f) नये ः थल पर बसाहट तब तक नहीं की जावेगी जब तक ः थल पर भूमि का आबंटन एवं उनको ूदत् त सुविधा की व् यवः था पूणर् न कर ली हो परन् तु यह भी वनूाणी संरक्षित ः थल से वन ूाणियों के संरक्षण हेतु अधिकार ूदत् त हटाये व् यक्तियों को नये ः थल से िकसी भी राज् य शासन या केन् ि शासन की िकसी योजना के अन् तर्गत पुनः नहीं हटाया जावेगा।

(3) वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के व् यक्त तथा अन् य वन में परम् परागत रहने वाले व् यक्तियों को िकसी राज् य या संघ शासित ूदेश में वन में अधिकारों को मान् य करना तथा वेिष्ठत करना इसी शतर् के अध् याधीन है िक उन् होने 13 िदसम् बर 2005 को वन भूमि पर कब् जा कर िलया था।

(4) उपधारा (1) के अन् तर्गत ूदत् त अधिकार उत् तरािधकाराधीन है लेिकन हः तान् तरणीय या अन् यसबमणीय नहीं है। यह अधिकार शादीशुदा व् यक्त के मामले में पित तथा पित्र के नाम पर और अकेले व् यक्त के मामले में व् यक्त के नाम पर पंजीकृत िकिया जावेगा तथा उत् तरािधकारी को हः तान् तिरत हो जावेगा तथा यदि सीधे उत् तरािधकारी न हो तो अगले नए िरै तेदार को ः थानान् तिरत होगा।

(5) वन में रहने वाले िकसी अनु.जनजाति या अन् य पराम् परागत वन में रहने वाले व् यक्तियों वन भूमि से बेदखल या उसे वन से इस िनयमों के ूावधान के अतिरक् त भगाया नहीं जावेगा जब तक अधिकारों की मान् यता तथा उसका सत् यापन पूरा न हो जावे।

(6) जब वन के अधिकारों को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपधारा (a) की वनभूमि पर मान् यता दी जावे और उन् हें वेिष्ठत िकिया जावे तब वह भूमि उस व् यक्त या पिरवार या समुदाय के कब् जे में, इस अधिनियम के लागू होने के िदनांक से रहेगी, और यह अधिकार केवल उतनी ही भूमि पर या अधिकतम 4 हेक् टयर तक सीमित रहेगी। िजस पर उनका कब् जा था।

(7) ये वन के अधिकार सभी िवलंगमों से रिहत तथा िकसी ूबिया के िबना ूदाय िकये जावेंगे। िजसमें वनों की सफाई पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 180 के अन् तर्गत, अनुमित सिम्मिलत रहेगी लेिकन भूमि धारी को भूमि का 'आज का शुद्ध मूल् य' तथा वन भूमि के पिरवर्तर्न के कारण 'ूितकरात् मक वन रोपण' का व् यय का भुगतान करना होगा।

(8) इस अधिनियम के अन् तर्गत अधिकारों की मान् यता तथा ूदाय उन अनुसूचित जनजाति के सदः य तथा परम् परागत वन में रहने वाले व् यक्तियों को भी देय होंगे, जो यह ूमाणिता कर सकें िक वे अपने ः थान से तथा कृषि भूमि से, राज् य के िवकास कायर् के िलये भूमि की आवँ यकता के कारण बेदखल िकये गये तथा उन् हें कोई अन् य भूमि नहीं दी गई है, लेिकन वह भूमि िजस पर से उन् हें हटाया गया है, उनको हटाने के 5 वषर् बाद भी कोई कायर् िजस हेतु अधिमहण की गई, नहीं हुआ है।

धारा 5. वन अधिकारों के धारकों के कत् तर्व् य - वन अधिकारों के धारक, तथा उस गांव िजसके रहवासियों को इस अधिनियम के अन् तर्गत अधिकार िदये गये हैं, की माम सभा, तथा अन् य गांव की संः थाओं को िनम् न अधिकार िदये जाते हैं -

- (a) वन ढाणी, वन, तथा वन के िविशं ट पौधे या वन पशु की सुरक्षा करना
- (b) क्षेS के जलमहण क्षेS, जल ऊँोत और अन् य पर्यावरण संवेदनशील क्षेSों की रक्षा करना।
- (c) वन में रह रहे अनु.जनजाति के एवं अन् य परम् परागत वनवासियों के आसपास के पर्यावरण पर कोई िवनाशकारी कायर् न हो जो उनके सां: कृितक एवं ढाकृितक िवरासत पर ढूभाव डाले, यह सुनिश्चित करें।
- (d) यह सुनिश्चित िकया जावे िक माम सभा द्वारा वनों में पहुँच सम् बन् धी िनणर्ण िलये जावे वे वन ढाणी, वन, वन के िविशं ट पौधे या पशु पर िवपरीत ढूभाव न डाले।

अध् याय IV

वन अधिकारों को ढूदाय करने की ढूबिया और अधिकारी

धारा 6. वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सद: य तथा अन् य व् यिक्तियों को वन के अधिकार देने वाले अधिकारी और अधिकार देने की ढूबिया - वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सद: यों तथा परम् परागत वन में रहने वाले अन् य व् यिक्तियों (एकल या सामूदायिक) वन को अधिकारों की ढूकृति (Nature) तथा सीमा को िनँ चत करने की ढूबिया उस माम सभा द्वारा, िजसकी सीमा में वह वनक्षेS आता है ढूारम् भ की जावेगी। माम सभा इस अधिनयम के अन् तर्गत दावों को ढूापू त करेगी, उसको संकिलत करेगी उनकी जांच करेगी तथा वह ढूत् येक व् यिक्त को िजस क्षेS पर अधिकार देने की िसफारिश करेगी उसको मानिचS में ढूदिशर्त करेगी। तथा यह रीति िनधारित करेगी जो िजससे वह अधिकार का उपयोग हो। इसे पँ चात् एक ढूः ताव पारित करेगी और ढूः ताव की एक ढूति उप मण् डलीय कमेटी को भेजेगी।

(2) िद कोई व् यिक्त माम सभा के ढूः ताव से व् यिथत हो तो वह ढूः ताव के िवरुद्ध उपधारा (3) के अन् तर्गत गिठत सबिडवीजनल लेबल कमेटी को आवेदन ढूः तुत करेगी। सबिडवीजनल कमेटी उस पर िवचार करेगी तथा आवेदन का िनराकरण करेगी।

परन् तु ऐसा आवेदन, मामसभा द्वारा ढूः ताव पारित करने के 60 िदन के अन् दर ढूः तुत िकया जा सकेगा। परन् तु ऐसा कोई भी आवेदन, व् यिथत आवेदक के िवरुद्ध तब तक नहीं िनराकृत िकया जावेगा जब तक उसको अपना पक्ष ढूः तुत करने का अवसर न िदया जावे।

(3) राज् य सरकार सबिडवीजनल लेवल कमेटी गिठत करेगी जो माम सभा द्वारा पारित ढूः ताव पर िवचार करेगी, और वन अधिकारों का िरकाड् तैयार करेगी और उनको सबिडवीजनल आफसर के माध् यम से िडवीजल लेवल कमेटी का अमेिषत करेगी।

(4) ऐसा व् यिक्त, जो सब िडवीजनल लेवल कमेटी के िनणर्ण से व् यिथत हो, वह उसके िनणर्ण के िवरुद्ध, िडि:शक् ट लेवल कमेटी को, सबिडवीजनल लेबल कमेटी के िनणर्ण के िदनांक से, 60 िदन के अन् दर आवेदन कर सकेगा तथा िडि:शक् ट लेवल कमेटी उस पर िवचार कर उसका िनराकरण करेगा।

परन् तु कोई भी आवेदन, माम पंचायत के ढूः ताव के पँ चात् , सीधे िडि:शक् ट लेवल कमेटी को ढूः तुत नहीं िकया जा सकेगा, जब तक वह सब िडवीजनल लेवल कमेटी को ढूः तुत नहीं िकया जावे। और उसका िनणर्ण न हो जावे।

परन् तु यह और भी िक िकसी भी आवेदन का िनराकरण आवेदक के िवरुद्ध तब तक नहीं िकया जावेगा, तब तक आवेदक को अपना पक्ष ढूः तुत करने हेतु समुचित अवसर न िदया जावे।

(5) राज् य सरकार एक िडि:शक् ट लेवल कमेटी गिठत करेगी जो सब िडवीजनल लेवल कमेटी द्वारा तैयार िकये वन अधिकारों के अभिलेख पर िवचार करेगी और अन्तम रूप से ः वीकार करेगी।

(6) इस ढूकार िडि:शक् ट लेवल कमेटी का वन अधिकारों के अभिलेख के सम् बन् ध में िलया िनणर्ण अन्तम और बाध् यकारी होगा।

(7) राज् य सरकार, राज् य ः तर पर, एक ः टेट लेबल मािनटिरंग कमेटी गिठत करेगी, तो वन अधिकारों की मान् यता देने तथा ढूदान करने की ढूबिया पर िनगरानी रखेगी और नोडल एजेन् सी द्वारा मांगी गई िरपोटर् या िरटनर् ढूः तुत करेगी।

(8) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडि:शक् ट लेवल कमेटी तथा ः टेट लेवल मािनटिरंग कमेटी में राज: व, वन तथा आदम जाति कल् याण िवभाग के अधिकारी रहेंगे। तथा तीन सद: य, उचित ः तर के, पंचायती राज् यसं: था द्वारा िनयुक् त िकये जावेंगे िजनमें दो अनुसूचित जनजाति के तथा एक मिहला सद: य होगी।

(9) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडि:शक् ट लेवल कमेटी और राज् य ः तरीय मािनटिरंग कमेटी की संरचना और उसके कायर् करने में अपनाई जाने वाली ढूबिया वह होगी जो िनधारित की जावे।

अध् याय V

अपराध एवं दण् ड

धारा 7. इस अधिनयम के अन् तर्गत सद: य, या अधिकारी, और ढूाधिकारी और कमेटी द्वारा अपराध - जब कोई ढूाधिकारी या कमेटी या अधिकारी या सद:य, इस अधिनयम के िकसी ढूावधान या इसके अन्तर्गत बने िनयमों के

व्यावधानों का, अधिकारों की मान्यता देने में उल्लंघन करता है तब वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी माना जावेगा और उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही हो सकेगी और वह एक हजार रुपये तक दण्ड का भागी होगा।

परन्तु व्याधिकारी का कोई भी सदःय, या कमेटी या विभाग मुख या और कोई व्यक्ति जो इस धारा में सन्दिर्भत किया गया है और दण्ड का भागी है, को कोई दण्ड नहीं दिया जावेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और उसने ऐसा अपराध को न होने देने के लिए तत्परतापूर्वक समःत आवश्यक कार्यवाही की थी।

धारा 8. अपराध का संज्ञान - कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम की धारा 7 के अन्दर, अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक वन में रहने वाला अनुसूचित जनजाति का सदःय, माम सभा के व्यावधान या माम सभा के किसी उच्च अधिकारी के विरुद्ध व्यावधान के विरुद्ध राज्य मानिटिरिंग कमेटी को 60 दिन की अवधि का नोटिस नहीं देता है, और राज्य मानिटिरिंग कमेटी ने उसे विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है।

अध्याय VI

विविध

धारा 9. व्याधिकारी के सदःय आदि लोक सेवक होंगे - अध्याय IV में सन्दिर्भत व्याधिकारियों के सदःय और अन्य अधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार व्याप्योजित किये हैं, वे भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक होंगे।

धारा 10. सदभाव से किये कार्यों के लिए सुरक्षा - (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने के इरादे से किये किसी कार्य के लिए केन्शिसन या राज्य शासन के कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, कार्यवाही या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने के इरादे से किये कार्य से हुई कोई क्षति या संभावित क्षति के विरुद्ध केन्शिसन, राज्य शासन या उसके कोई अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने से किये गये किसी कार्य के विरुद्ध अध्याय IX के अन्तर्गत गिठत किसी व्याधिकारी, अध्यक्ष, सदःय, सदःय सचिव एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

धारा 11. नोडल एजेन्सी - केन्शिसन का वह मन्डाल, जो अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी कार्य देखता है या कोई अधिकारी कोई व्याधिकारी जिसे केन्शिसन द्वारा इस हेतु व्याधिकृत किया जावे वह इस अधिनियम के व्यावधान लागू करने हेतु नोडल एजेन्सी होगी।

धारा 12. केन्शिसन के निर्देश देने के अधिकार - इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना कर्तव्य पालन करने तथा इसके द्वारा या इसके अन्तर्गत अधिकार का उपयोग करने हेतु, अध्याय IV के अन्तर्गत सन्दिर्भत व्याधिकारी, केन्शिसन के लिखित आदेशों का, जो समय समय पर जारी किये जावे, के अध्याधीन कार्य करेंगे।

धारा 13. इस अधिनियम के कार्य अन्य कानूनों का अल्पीकरण नहीं करेंगे - इस अधिनियम तथा पंचायत अधिनियम 1996 में अन्यथा व्यावधानित के अतिरिक्त इस अधिनियम के व्यावधान, अन्य कानूनों के, जो उस समय लागू हो, के सहायक होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं होंगे।

धारा 14. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्शिसन, अधिसूचना जारी कर, तथा इसको लागू करने के पूर्व प्रकाशन कर, इस अधिनियम के व्यावधान लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप में तथा पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर रूतकूल भाव डाले बिना, ऐसे नियम, समःत या निम्न में से किसी विषय को उपबन्धित करेंगे।

(a) धारा 6 में निर्धारित रूबिया तथा उसको लागू करने की रूबिया का ब्योरा।

(b) अधिनियम के नियम (6) के उपनियम (1) के अन्तर्गत दावे प्राप्त करने, उनको संकलित करने, उसका सत्यापन करने और सिफारिश किये दावे के क्षेत्र को वन अधिकारों का उपभोग करने हेतु मानिचऽ में अंकित करने तथा सब िडवीजनल कमेटी को धारा 6 उपनियम (2) के अन्तर्गत आवेदन देने की रूबिया निर्धारित करना।

(c)

धारा 6 उपनियम 8 के अन्तर्गत सब िडवीजनल कमेटी, िडिशक्त लेवल कमेटी तथा ंटेड लेवल मानिटिरिंग कमेटी में राजःव, वन, आदम जाति विभाग के किस ंतर के अधिकारियों को सदःय नियुक्त करने विषयक।

(d) सब िडवीजनल लेवल कमेटी, िडिशक्त लेवल कमेटी और ंटेड लेवल मानिटिरिंग कमेटी की संरचना और उनके धारा (6) उपधारा (9) के अन्तर्गत कर्तव्य और उनके कर्तव्य पालन की रूबिया।

(e) अन्य कोई विषय जिसको करने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता हो, के विषय में रूबिया।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्शिसन द्वारा बनाया कोई नियम, उसको बनाने के पश्चात् तथा सम्भव शीघ्र, संसद के रूयेक सदन में, जब वह 30 दिन का अधिवेशन एक साथ होया 2 या 3 लगातार सेशन में हो, रूतुत किया जावेगा तथा अधिवेशन की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन इसमें कोई संशोधन करना चाहे या और यदि दोनों सदन की राय हो कि यह

नियम नहीं बने तब तक नियम संशोधित रूप से लागू होगा या नहीं होगा और इसके पूर्व किये कार्यों की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी।

